जज डी वी सेगल
जसवंत सिंह और अन्य, याचिकाकर्ता।
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य, उत्तरदाताओं।
1988 की सिविल रिट याचिका नंबर 1022।
5 मई, 1988।

भारत का संविधान, 1950-आर्ट्स। 14, 15 (1)-शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा में प्रवेश करने के लिए, हरियाणा-प्राथमिकता के निवासियों को मेवाट क्षेत्र के उम्मीदवारों को 10 अंकों के आवंटन के लिए इस तरह के उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है, चाहे वह आवंटित हो। इस तरह के आधार पर प्रवेश की साक्षात्कार-वैलिडिटी के लिए प्रत्येक उम्मीदवार पर खर्च किए गए 45 सेकंड का साक्षात्कार।
हेल्ड, कि प्रत्येक उम्मीदवार को आवंटित 10 अंक जो मेवाट क्षेत्र के अधिवास थे, पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं। यह न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के अल्ट्रा-पोत्स भी हैं, मेवाट क्षेत्र के अधिवास के लिए 10 अंकों का आवंटन 50 प्रतिशत के खिलाफ उम्मीदवारों का चयन करते हुए 50 प्रतिशत का चयन करते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए सीटों में वायरल-टालो के परिणामस्वरूप सीटों का 100 प्रतिशत आरक्षण होता है जो कि अन-संवैधानिक है। इसलिए, समान नहीं किया जा सकता है।
(पारस 17 और 18)

हेल्ड, कि चयन समिति ने प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार करने के लिए एक मिनट से भी कम समय बिताया। अधिक सटीक होने के लिए, इसने प्रत्येक उम्मीदवार पर औसतन 45 सेकंड बिताए। अब समिति को प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम तीन पहलुओं पर अपने व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए अंतर करना था; काया, बुद्धिमत्ता और उपयुक्तता। कैसे, समिति इसे प्रति उम्मीदवार 45 सेकंड में कर सकती है और फिर मार्क्स बोगल्स कल्पना को आवंटित कर सकती है। जैसे कि कमेटी द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार, एक मात्र फारस था और इस तरह के प्रत्येक उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए आवंटित किए गए अंक पूरी तरह से मनमाना

और सनकी थे।
(पारस 11 और 12)

भारत के संविधान के 226/227 लेखों के तहत सिविल रिट याचिका प्रार्थना करते हुए:-

(i) मामले के पूर्ण रिकॉर्ड को बुलाया जाना चाहिए;
(ii) इस माननीय अदालत को 21 दिसंबर, 1987, 22 दिसंबर, 1987, 23 दिसंबर, 1987 को किए गए साक्षात्कारों के आधार पर सत्र 1987-89 के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स के लिए किए गए चयन को कम करने के लिए प्रसन्नता हो रही है। और 24 दिसंबर, 1987;
(iii) शिक्षा पाठ्यक्रम, 1987-89 मेरिट के अनुसार
मैट्रिक या उच्च योग्यता में उनके द्वारा प्राप्त डिप्लोमा के लिए मंडामस की प्रकृति में एक रिट जारी की जानी चाहिए।
(iv) यह माननीय अदालत भी किसी भी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश दिशा को फिट और उचित रूप से परिधि में उचित रूप से जारी कर सकती है-
मामले के रुख;
(v) याचिका की लागत भी सम्मानित की जाती है;
(vi) अनुलग्नक p/1 की प्रमाणित प्रति के दाखिल करने के बारे में शर्त के साथ dishensed;
(vii) रिट की अग्रिम सूचना की सेवा के बारे में स्थिति
याचिका को भी भेज दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए एस.एस. निज्जर, अधिवक्ता।
एम। एस। जैन, एडल। उत्तरदाताओं के लिए विनी जैन, वकील के साथ ए.जी. (एच)।

प्रलय

जज डी वी सहगल
यह निर्णय सिविल रिट याचिका नं। 791, 792, 1022, 1114, 1145 और 1394 का 1988 का निपटान करेगा। इन सभी याचिकाओं को डिप्लोमा इन एजुकेशन

कोर्स 1987-89 सत्र में प्रवेश के लिए चयन के खिलाफ सरकार जे.बी.टी. स्कूल, फेरोज़ेपुर नामक (गुड़गांव)। इसलिए इन्हें एक साथ निपटाया जा रहा है। पार्टियों, तथ्यों और दस्तावेजों का संदर्भ जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, 1988 के सिविल रिट याचिका नंबर 1022 से बनाया जाएगा।

(2) उत्तरदाताओं को प्रॉस्पेक्टस, अनुलग्नक पी. 1 जारी कर
"डिप्लोमा" नामक शिक्षा पाठ्यक्रम में (हिन्दी और उर्दू) डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन सरकारी जे.बी.टी. स्कूल, फेरोज़ेपुर नामक (गुड़गांव) में आमंत्रित किया गया । अनुलग्नक में दिए गए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, p.1 मैट्रिक/ उच्चतर माध्यमिक भाग- । या किसी अन्य समकक्ष परीक्षा है। एक और शर्त यह है कि एडमिस-सायन की तलाश करने वाले उम्मीदवार को हरियाणा का एक बोनफाइड निवासी होना चाहिए। यह आगे की बात है- एड कि वरीयता गुड़गांव और फरीदाबाद के मेवाट क्षेत्र के बोनफाइड उम्मीदवारों को दी जाएगी। उम्मीदवारों को निर्धारित रूपों पर अपने आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जो कि प्रतिवादी नंबर 4 से रुपये में सक्षम थे। 3 प्रति फॉर्म। अनुप्रयोगों को डुप्लिकेट में प्रतिवादी नंबर 4 को प्रतिवादी नंबर 4 के लिए एक प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना था। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 1987 थी। याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए उक्त पाठ्यक्रम के लिए। जिन सभी उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा किए थे, उन्हें अनुवर्ती तारीखों पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता थी:--
(i) सभी महिला उम्मीदवार (हिंदी और उर्दू)
21.12.1987
(ii) पुरुष उम्मीदवार (उर्दू)
22.12.1987
(iii) पुरुष उम्मीदवार (हिंदी) 1-500 से
23.12.1987
(iv) बाकी उम्मीदवार।
24.12.1987

याचिकाकर्ताओं के पास पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता थी। उन्होंने निर्धारित तिथि द्वारा निर्धारित फॉर्म पर अपने आवेदन प्रस्तुत किए। यह औसत है कि 15,000 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उनमें से 10,000 हिंदी पाठ्यक्रम के लिए और उर्दू पाठ्यक्रम के लिए 5,000 थे।

(३) पाठ्यक्रम के लिए सभी २०० सीटें थीं, उनमें से १०० सीटें हिंदी पाठ्यक्रम के लिए थीं और १०० उर्दू पाठ्यक्रम के लिए थीं।

(४) याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें इस तथ्य के बावजूद नहीं चुना गया था कि उन्होंने उच्च अंकों के साथ मैट्रिकुलेशन/ उच्च माध्यमिक भाग-आई परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनमें से कुछ स्नातक भी थे, प्रभाकर या संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे। यह आरोप लगाया जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित साक्षात्कार एक दूरदराज था और साक्षात्कार के परिणामस्वरूप अलग -अलग उम्मीदवारों को आवंटित किए गए अंक केवल पसंदीदा उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए चयन करने के लिए एक छलावरण थे। यह उनके द्वारा आगे कथित है कि मेवाट क्षेत्र के उम्मीदवारों को कोई वरीयता नहीं दी जा सकती है। इस तरह की वरीयता संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उत्तरदाताओं ने केवल उन उम्मीदवारों में से प्रत्येक के लिए 10 अंक दिए, जो मेवाट क्षेत्र से थे, इस प्रकार उन्हें प्रवेश प्राप्त करने के लिए एक लाभप्रद स्थिति दे।

(५) १ ९ (of के सिविल रिट याचिका संख्या ११1४ में, याचिकाकर्ताओं ने चौधरी खुर्शीद अहमद, शिक्षा मंत्री, हरियाणा, प्रतिवादी नंबर ४ के खिलाफ मलाफाइड्स का आरोप लगाया है। सूची पक्षपात और भाई -भतीजावाद का परिणाम है। शैक्षणिक कैरियर में कम अंकों वाले उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए चुना गया है, जबकि उच्च अंक वाले लोगों को छोड़ दिया गया है। इस याचिका में, उत्तरदाताओं की संख्या 5 से 8 जो पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवार हैं, उन्हें भी निहित किया गया था। केपॉन्टेंट नंबर 4 ने अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें मालाफाइड के आरोप को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया गया। उन्होंने कहा है कि मेरिट सूची एक चयन समिति द्वारा तैयार की गई थी। उक्त सेलेक्शन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। इस श्रेणीबद्ध इनकार के मद्देनजर, मैं इसे पूरी तरह से संयुक्त रूप से मानता हूं, जो कि प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए

इन आरोपों में जाने के लिए आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों, उत्तरदाताओं के नंबर 5 से 8 को श्री एस। के। सरदाना, एडवोकेट द्वारा मेरे सामने विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था। और मैंने उनकी रक्षा पर विचार किया है।

(६) उत्तरदाताओं की ओर से लिखित बयान १ ९ of of सिविल रिट याचिका संख्या १०२२ में १ ९ 19888 में दायर किया गया था। तर्कों की शुरुआत से पहले, जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव, प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया है। यह औसतन है कि हिंदी पाठ्यक्रम और उर्दू पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक में से 100 सीटों में से प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित सीटें आरक्षित थीं। मानदंड/सूत्र के अनुसार विभिन्न श्रेणियां, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुलग्नक आर। ।।:--
(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।
इसे स्वीकार करो।
(ii) पिछड़े वर्ग।
10 प्रतिशत।
(iii) पिछड़े क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र (योग्यता मामलों की संख्या को छोड़कर)
13 प्रतिशत।
(iv) निर्जन / कानूनी रूप से तलाकशुदा / विधवा महिला उम्मीदवार।
2 प्रतिशत।
(v) बच्चे और सशस्त्र बलों के कर्मियों/पूर्व सैनिकों पर निर्भर।
5 प्रतिशत।
(vi) सामान्य।
50 प्रतिशत।
यह आगे के मानदंडों में उल्लेख किया गया है, एनेक्स्योर पी। ।। कि अधिकतम 45 अंकों को न्यूनतम योग्यता के लिए आवंटित किया गया था- मैट्रिकुलेशन/उच्च माध्यमिक भाग-आई । एक उम्मीदवार द्वारा इस तरह की परीक्षा से प्राप्त कुल अंकों में से, बाएं हाथ के 2 अंकों को 2 से विभाजित किया गया था ताकि न्यूनतम योग्यता के लिए उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले अंकों का काम किया जा सके यानी यदि किसी उम्मीदवार को 800 अंक प्राप्त हुए, तो 80 होना था। 2 से विभाजित और आवंटित किए जाने वाले निशानों को 40 के रूप में काम किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए 15 अंक आवंटित किए गए थे यानी उच्च माध्यमिक भाग- ।, इंटरमीडिएट /बी.ए. पार्ट-आई, बी.ए. और

एम। ए। एक और 5 अंक उन लोगों को सम्मानित किया जाना था, जिन्होंने अडीब आलम/प्रभाकर/शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की थी। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेल/सह-पाठ्येतर गतिविधियों आदि के लिए आवंटित 8 अंक। मैं यहां इंगित कर सकता हूं कि प्रत्येक उम्मीदवार को उपर्युक्त प्रत्येक को आवंटित किए जाने वाले अंकों को बाहर करने के लिए सूत्र को मेरे सामने चुनौती नहीं दी गई है।

(7) हालाँकि, मानदंड में, अनुबंध आर ।।, साक्षात्कार के लिए 12 अंक आवंटित किया गया थे अर्थात उम्मीदवारों की उपयुक्तता, शारीरिक बनावट और बुद्धि आदि का परीक्षण करना। मेवाट क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों के लिए और 10 अंक आवंटित किए गए थे। यह इन दो श्रेणियाँ हैं जो उम्मीदवारों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए तय किए गए हैं, जो प्रवेश के लिए चुने जाने के लिए हैं जो मेरे सामने विवाद का विषय है।

(8) प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में, यह बताया गया है कि शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी और उर्दू दोनों में प्रवेश के लिए 7820 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था । उनमें से 5580 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। यह और अधिक औसत किया गया है कि साक्षात्कार 21 वीं डेसम-बेर, 1987 से 25 दिसंबर, 1987 से 5 दिनों पर आयोजित किए गए थे, जिसमें एक चयन समिति द्वारा एक अध्यक्ष और नीचे नामित तीन सदस्य शामिल थे:-

(i) श्री डी.एस. प्रमार, जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव।
अध्यक्ष।

(ii) श्री डब्ल्यू। आर। गुप्ता, उप-डिविसियो- नाल शिक्षा अधिकारी, नुह।
सदस्य।

(iii) श्री एन.डी. सूदन, प्रधानाध्यापक,

सरकारी जे.बी.टी. स्कूल,

फ़िरोज़पुर नमक (गुड़गांव) सदस्य।

(iv) श्रीमती कुसुम लता, हेड मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट गर्ल्स

हाई स्कूल, नूंह

सदस्य।

(९) यह कहा गया है कि समिति ने 5580 उम्मीदवारों में से प्रत्येक को उनके साक्षात्कार के बाद अंक आवंटित किया है और कोई फ़ेवोर्टिज़्म नहीं दिखाया गया है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं में से कई को साक्षात्कार के लिए 12 अंकों के कान में से 8 से 11 अंकों से सम्मानित किया गया था।

(१०) इस आरोप के संबंध में कि मेवाट क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए १० अंकों का आवंटन भेदभावपूर्ण है, यह कहा गया है 1988 के सिविल रिट याचिका नंबर 1114 में लिखित बयान में कि मेवाट क्षेत्र के उम्मीदवारों को वरीयता/प्राथमिकता दी गई है क्योंकि उक्त क्षेत्र पिछड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी पर्याप्त पुन: प्रस्तुति नहीं है। यह आगे समझाया गया है कि सरकार उस क्षेत्र के शिक्षकों को वहां सेवा करने में बहुत कठिनाई महसूस करती है। इसलिए, इस क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया ताकि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, सफल उम्मीदवार वहां स्थित स्कूलों में सेवा कर सकें। दी गई वरीयता इस आधार पर उचित है कि यह बड़े सार्वजनिक हित में और मेवाट क्षेत्र के निवासियों के हित में था।

(११) मैंने पार्टियों के लिए सीखा वकील सुना है। मैं इस विचार का विचार कर रहा हूं कि समिति द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक मात्र भयावह था और जैसे कि साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों में से प्रत्येक को आवंटित किए गए अंक पूरी तरह से मनमाना और सनकी थे। मेरे दिमाग में यह भी कोई संदेह नहीं है कि मेवाट क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 10 अंकों का आवंटन पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था और उन उम्मीदवारों के लिए

अन्याय काम करता था जो उस क्षेत्र से संबंधित नहीं थे। मेवाट क्षेत्र से संबंधित नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन की संभावना इस प्रकार लगभग गैर-मौजूद थी।

(१२) मैं सबसे पहले पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार की वैधता और उन्हें आवंटित अंक के सवाल पर आता हूं। यह उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए 5,580 आवेदक दिखाई दिए। 21 दिसंबर, 1987 से 25 दिसंबर, 1987 तक पांच दिनों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। सीखा अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल, हरियाणा ने प्रस्तुत किया कि चयन कॉम-मिती ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने के लिए प्रत्येक दिन 12-14 घंटे समर्पित किया। मैं इसे लेता हूं कि प्रत्येक दिन, चयन समिति ने उद्देश्य के लिए 14 घंटे के रूप में समर्पित किया और प्रति दिन इन 14 घंटों में उन्होंने प्रति दिन 1116 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। इसका मतलब यह होगा कि चयन समिति ने प्रत्येक उम्मीदवार का साक्षात्कार करने के लिए एक मिनट से भी कम समय बिताया। अधिक सटीक होने के लिए, इसने प्रत्येक उम्मीदवार पर औसतन 45 सेकंड बिताए। अब समिति को प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम तीन पहलुओं, काया, बुद्धिमत्ता और उपयुक्तता पर अपने व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए कम से कम साक्षात्कार करना था। समिति 45 सेकंड में प्रति उम्मीदवार कैसे कर सकती है और फिर मार्क्स बोगल्स कल्पना को आवंटित करती है। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित अवलोकन, (1)अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य में बताया हैं साक्षात्कार आयोजित कैसे किया जाना चाहिए और आम तौर पर कितना समय लेने की संभावना है:-

"यह देखना वास्तव में मुश्किल है कि कैसे ठीक से और संतोषजनक रूप से एक कैंडी तिथि के व्यक्तित्व को आश्वस्त करने के लिए एक विवा-वोस परीक्षण किया जा सकता है, अगर 1,300 से अधिक उम्मीदवारों को एक सेवा में भर्ती के लिए साक्षात्कार दिया जाए। पूरी तरह से और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक उम्मीदवार के व्यक्तित्व के निष्पक्ष और संतोषजनक मूल्यांकन पर पहुंचने के लिए होना चाहिए, साक्षात्कार को 10-30 मिनट के बीच कोई भी चीज लेना चाहिए। वास्तव में, हरमन में महीन "थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट" पर उनकी पुस्तक बताती है कि "साक्षात्कार कम से कम आधे घंटे तक चलना चाहिए"। कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयन करने वाले संघ लोक सेवा आयोग ने लगभग आधे घंटे के लिए एक कैन-डिडेट का साक्षात्कार किया। केवल 11-12 उम्मीदवारों को 5 घंटे के दिन में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह स्पष्ट है कि परिस्थितियों में, एक संतोषजनक विवा-वोस परीक्षण करना असंभव होगा यदि 1,300 से अधिक उम्मीदवारों की इतनी बड़ी असहनीय संख्या होनी चाहिए साक्षात्कार किया। तब साक्षात्कार आकस्मिक, सतही और मैला होंगे और इस तरह के साक्षात्कारों में किए गए मूल्यांकन से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के सही माप को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसा पाठ्यक्रम मनमानी के क्षेत्र को चौड़ा करेगा। यहां तक कि एक ऐसे उम्मीदवार के लिए, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त निशानों के आधार पर सूची में बहुत कम है, जो कि डिवीजन बेंच द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति को उधार लेने के लिए, 'गेट-क्रैश' को चयन की सीमा में

उधार लेने के लिए कर सकता है। उन्हें मौखिक परीक्षा में उच्च अंक से सम्मानित किया जाता है। "

(१३) इस पर विचार किया जाने वाला एक और पहलू यह है कि क्या साक्षात्कार कच्चे-मैट्रिकुलेट्स के मामले में सभी उचित था, जिन्हें पाठ्यक्रम में भर्ती किया जाना था। लीला धर बनाम राजस्थान राज्य में, (2) एक कॉलेज में प्रवेश के मामले में भी, अंतिम अदालत ने देखा है कि उम्मीदवारों का व्यक्तित्व अभी तक विकसित होना है और यह व्यक्तिगत गुणों की पहचान करने के लिए बहुत जल्दी जिसके लिए अधिक से अधिक im-portance को बाद के जीवन में संलग्न किया जा सकता है, लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक वजन को दिया जाना है। साक्षात्कार से जुड़ा होने का महत्व न्यूनतम होना चाहिए।

(१४) साक्षात्कार के लिए आवंटित १२ अंकों को फिर से जोड़ना उन्हें मैट्रिकुलेशन में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक के साथ समता में लाने के लिए/उच्चतर माध्यमिक भाग-आई परीक्षा में उपरोक्त सूत्र पर परीक्षा के साथ, यह पाया जाएगा कि यह पाया जाएगा कि 900 अधिकतम अंकों की तुलना में। पूर्वोक्त न्यूनतम योग्यता, 240 अंक लगभग साक्षात्कार के लिए आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार, साक्षात्कार में प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए निशानों का उद्देश्य योग्यता में योग्यता और प्रदर्शन में योग्यता को योग्यता में परिवर्तित करना था। इन-टेरव्यू के लिए आवंटित किए गए निशान अधिकतम 45 अंकों के 25 प्रतिशत से अधिक हैं, जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए थे, जो किसी भी मामले में टिकाऊ नहीं हो सकता है।

(१५) विभिन्न उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आवंटित किए गए अंकों के बारे में चार्ट के माध्यम से जाने पर और उन लोगों के साथ प्रवेश के लिए चुने गए उम्मीदवारों के विशेष मामलों की तुलना करना, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण हैं जहां एक उम्मीदवार ने बहुत उच्च अंक हासिल किए हैं। साक्षात्कार में बहुत कम अंक देकर मैट्रिक परीक्षा को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके विपरीत, एक उम्मीदवार ने मातृ-कलेशन परीक्षा में बहुत कम अंक हासिल किए हैं, उन्हें साक्षात्कार में तुलनात्मक रूप से उच्च अंक दिए गए थे ताकि उन्हें योग्यता पर उच्च स्थान दिया जा सके ताकि

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनके चयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। यदि मैं इनमें से कुछ को रुख करता हूं, तो इसके परिणामस्वरूप विकृतियों की सीमा को कम किया जाएगा, जो विभिन्न संघनितों के लिए साक्षात्कार के निशान आवंटित करके लाया गया है।

(१६) सीखा अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल, हरियाणा, में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे उदाहरणों को इंगित किया गया है, जहां कुछ अस्वीकृत उम्मीदवारों को साक्षात्कार में 11 अंक आवंटित किए गए हैं। वास्तव में, ये उन उम्मीदवारों के मामले हैं, जिन्होंने मैट्रिकेशन परीक्षा में बेहद कम अंक हासिल किए थे और यहां तक कि 11 अंकों को जोड़कर, वे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चुने जाने के लिए योग्यता में पर्याप्त जगह नहीं पा सकते थे। यह वास्तव में पूरी तरह से मनमानी और मितव्ययी तरीके से दिखाता है जिसमें साक्षात्कार के लिए अंक चयन समिति द्वारा आवंटित किए गए हैं। मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि रेस-पॉन्डेंट्स की ओर से उद्धृत उदाहरणों का उद्देश्य केवल यह मानने के लिए भोला-भाला लेने के उद्देश्य से है कि चयन समिति अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों को टेरव्यू के निशान आवंटित करने में निष्पक्ष और उदार थी। यह बल्कि दर्शाया गया है बदसूरत तरीके से हेरफेर किया गया है। मुझे इस मामले पर आगे पतला करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि समिति के सदस्यों के व्हिम और कैप्रीस में विभिन्न उम्मीदवारों को दिए गए हैं, जो उन लोगों के सेलेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए थे, जिन्हें यह पाठ्यक्रम और उन लोगों की अस्वीकृति के लिए स्वीकार करना चाहता था, जिन्हें यह करना चाहता था प्रवेश से बाहर करें।

(17) अब इस मामले के दूसरे पहलू पर आकर, मैं फिर से अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट हूं कि प्रत्येक कैंडि-डेट्स को आवंटित किए गए 10 अंक जो मेवात क्षेत्र के अधिवास थे, पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं। उत्तरदाताओं की व्याख्या कि मेवाट क्षेत्र शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इन अंकों के आवंटन को सही नहीं ठहरा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए कुल सीटों का 50 प्रतिशत आरक्षित करते समय, 13 प्रतिशत सीटें पिछड़े क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवार फ्रॉर्न मेवाट क्षेत्र को इन आरक्षित सीटों के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत सीटों के

खिलाफ उम्मीदवारों का चयन करते हुए मेवाट क्षेत्र के अधिवास के लिए 10 अंकों का आवंटन लगभग 100 प्रतिशत सीटों के आरक्षण में फिर से किया गया है जो कि असंवेदनशील है। मुझे पी। राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य (3) ए। पेरियाकरुप्पर बनाम टी। एन। एन। (4) और महाराष्ट्र बनाम राज कुमार, (5) से इस दृष्टिकोण के लिए समर्थन मिला।

(18) अभ्यर्थियों के लिए तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर
सामान्य वर्ग में मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश एक भी अभ्यर्थी मेवात क्षेत्र से बाहर नहीं है। मेवाट क्षेत्र के उम्मीदवारों को 10 अंकों का आवंटन लगभग उन्हें 200 अंकों की कूद देता है (जब हम इन अंकों को मैट्रिकुलेशन या इक्विवा-लेंट परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक के साथ समता में लाने के लिए परिवर्तित करते हैं) मेवाट क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवारों पर । इसलिए, प्राकृतिक परिणाम यह था कि मेवाट क्षेत्र के बाहर से एक भी उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में भर्ती नहीं किया गया था। मेवाट क्षेत्र के उम्मीदवारों को इन अंकों का आवंटन पूरी तरह से मनमाना है। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अल्ट्रा वायरस भी है। इसलिए, समान नहीं किया जा सकता है।

(19) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं इन याचिकाएँ की अनुमति लागत सहित देता हूं , सरकारी जे.बी.टी. विद्यालय, फिरोजपुर नमक (गुड़गांव) में डिप लोमा इन एजुकेशन कोर्स 1987-89 में प्रवेश के लिए चयन को रद्द करें। मैं मेरिट क्षेत्र के लिए कोई भी वेटेज दिए बिना मेरिट सूची को तैयार करने के लिए उत्तरदाताओं की संख्या 1 से 4 को निर्देशित करता हूं और साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार को अंतर-दृश्य के लिए आवंटित किए गए अंकों को छोड़कर। प्रवेश के लिए योग्यता सूची उपरोक्त दिशाओं के अनुसरण में तैयार की जानी चाहिए और पाठ्यक्रम के लिए विज्ञापन-मिशन आज से एक महीने के भीतर इसके आधार पर किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक रिट याचिका में लागतों का मूल्यांकन 500 रुपये में किया जाता है।

जज आई एस तिवाना

पंजाब राज्य भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के माध्यम से, - अपीलकर्ता

बनाम
गुरबचन सिंह और अन्य, -सोन्सेंटेंट्स।
1979 की नियमित पहली अपील संख्या 1628।
और 1980 के क्रॉस-ऑब्जेक्ट्स नंबर 15-सी-आई।
27 जुलाई, 1988।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) एस.एस. 23 (1 ए), 23 (2) और 28 कॉम- पल्सरी अधिग्रहण मुआवजा मुआवजा-बाजार मूल्य-क्षति-धारा 23 (1 ए) और 23 (2) के फिट-क्या केवल बाजार मूल्य पर देय है।
हेल्ड, कि नुकसान की मात्रा को संभवतः बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, धारा 23 (1-ए) और सब-सेक्शन (2) के रूप में परिकल्पित अतिरिक्त राशि और सोलैटियम केवल धारा 23 के खंड (i) के तहत निर्धारित बाजार मूल्य पर केवल देय हैं और निर्धारित की गई राशि पर नहीं हैं। इस उप-खंड के तीसरे खंड के तहत। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 द्वारा परिकल्पित ब्याज, निश्चित रूप से मुआवजे की पूरी राशि पर देय है यानी बाजार मूल्य और अधिनियम की धारा 23 के खंड (2) के क्लॉज तीसरे खंड के तहत नुकसान।
(पारस 7 और 8)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

1.

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा